आत्मघाती परमाणु बिजली परियोजनायें

महाराष्ट्र के रत्नागिरी ज़िले में जैतापुर में परमाणु संयंत्र लगाने का तीव्र विरोध हो रहा है, बावजूद इसके महाराष्ट्र सरकार वहां फ्रांस की अरेवा कंपनी की मदद से बनने जा रहे 9,900 मेगावॉट की परमाणु बिजली परियोजना को शुरू करने पर आमादा है। इस परियोजना को केंद्र सरकार का पूरा समर्थन मिल रहा है। पर्यावरण एवं वन मंत्री जयराम रमेश ने कहा है कि यह परियोजना हर हाल में पूरी होगी। वे किसानों के विरोध को कोई महत्त्व देने के लिए तैयार नहीं हैं।

दूसरी तरफ, क्षेत्र के किसान और पर्यावरणविद व कार्यकर्ता इस परियोजना का उग्र विरोध कर रहे हैं। किसानों के विरोध का दमन करने के लिए पुलिस ने गोलियां तक चलाई जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। शिवसेना इस परियोजना के शुरू किये जाने का लगातार विरोध कर रही है। वह किसानों को भड़काने और छिटपुट हिंसा से भी बाज आने वाली नहीं है। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने 'सामना' में इस परियोजना को किसानों के हकों पर डाका बताया है। लेकिन जहां तक शिवसेना द्वारा इस परियोजना के विरोध का सवाल है, वह सिर्फ़ इसलिए विरोध कर रही है कि महाराष्ट्र की सत्ता उसके हाथ में नहीं है। शिवसेना का मुख्य लक्ष्य अपनी पार्टी के भगोड़े नारायण राणे पर प्रहार करना है जो इस क्षेत्र के विधायक और वर्तमान सरकार में उद्योगमंत्री हैं। शिवसेना सिर्फ़ राजनीतिक कारणों से विरोध कर रही है। उसे इस बात से कोई लेना-देना नहीं कि परमाणु बिजली घर पर्यावरण और आम आदमी के लिए कितने ख़तरनाक हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये परमाणु बमों से कम ख़तरनाक नहीं हैं। इसलिए दुनिया भर के पर्यावरणविद् और कार्यकर्ता परमाणु उर्जा का विरोध करते हैं। वे व्यापक जनहित में ऐसा करते हैं। पर जहां तक शिवसेना का सवाल है, इसकी साम्राज्यवादपरस्त विचारधारा और संर्कीण सांप्रदायिक दृष्टिकोण को देखते हुए यह समझ लेना चाहिए कि आज अगर यह सत्ता में होती तो इस परियोजना को लागू करवाती और इसके लिए किसानों का जिस हद तक दमन करना पड़ता, करती।

दूसरी तरफ़, किसान कम मुआवज़े और विस्थापन आदि समस्याओं के कारण इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। उस क्षेत्र की भूमि बड़ी उपजाऊ है और वहां विश्व प्रसिद्ध अल्फांसो आम पैदा होते हैं जिनकी मांग देश के साथ विदेशों में भी है। इसके अलावा परमाणु संयंत्र लग जाने पर मछुआरों के लिए समुद्र में मछली पकड़ पाना बंद हो जायेगा जो उनकी आय का एकमात्र साधन है। यही कारण है कि किसान एवं मछुआरे इस परियोजना के सख़्त विरोध में हैं।

लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान और उद्योग मंत्री नारायण राणे चाहे जैसे भी हो जैतपुर में इस परियोजना का काम पूरा करवाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें उनकी और केंद्र सरकार की साख भी दाव पर लगी हुई है, क्योंकि केंद्र सरकार और उड़ीसा सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद उड़ीसा में पास्को परियोजना किसानों के विरोध के कारण शुरू नहीं हो सकी। अगर जैतापुर में भी ऐसा होता है तो साम्राज्यवादी कारपोरेट कंपनियों का विश्वास सरकार पर नहीं रह जायेगा।

सिर्फ़ जैतापुर ही नहीं, देश के कई इलाकों में सरकार ने परमाणु बिजली घरों की स्थापना का निर्णय लिया है और इसके लिए अमेरिका, फ्रांस, इंगलैंड, जर्मनी आदि देश भारी कीमतों पर अपने पुराने पड़ चुके घटिया रियेक्टर बेचेंगे।

साम्राज्यवादी देशों के सरगना अमेरिका ने भारत के साथ जो विवादास्पद परमाणु समझौता किया था, उसमें देश में परमाणु रियेक्टर लगाये जाने की बात थी। इस परमाणु समझौते का विरोध केंद्र सरकार को समर्थन दे रहे वामपंथी दलों ने किया था और सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। इसके परिणामस्वरूप सरकार गिर सकती थी, पर सोनिया-मनमोहन की भ्रष्ट सरकार ने कतिपय सांसदों को खरीद कर अपनी सरकार बचा ली थी।

बहरहाल, वामपंथी अभी भी जोर-शोर से जैतापुर में और कहीं भी परमाणु संयंत्र लगाने का कड़ा विरोध कर रहे हैं, पर साम्राज्यवादी शक्तियों की हितपोषक, भ्रष्ट और तानाशाही प्रवृत्ति वाली सरकार के समक्ष किसी भी तरह का विरोध नक्कारखाने में तूती की आवाज़ बन कर रह जाता है। सरकार अपनी मनमानी करने में सफ़ल रहती है। इस मामले में भी ऐसा ही हो रहा है। वैसे, भारत में भी इतना वैज्ञानिक और तकनीकी विकास हो चुका है कि यहां के वैज्ञानिक अपने संसाधनों और तकनीकी क्षमता के बल पर परमाणु रियेक्टर बना सकते हैं। इसके लिए इन्हें किसी अन्य देश के सहारे की जरूरत नहीं है। पर अगर ऐसा होता है तो इस देश के शासक अपने साम्राज्यवादी मालिकों को अपने यहां लूट मचाने का मौका कैसे दे पायेंगे?

इस देश के और दुनिया के पर्यावरणवादी परमाणु उर्जा का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि यह आत्मघाती है। इसके आत्मघाती स्वरूप को 1986 में यूक्रेन (तत्कालीन सोवियत संघ का एक प्रांत) के चेर्नोबिल संयंत्र में देखा गया था जहां दुर्घटना के परिणामस्वरूप न जाने कितनी जानें गईं, उसका कोई हिसाब नहीं है। इस दुर्घटना के कारण सुदूर मध्य यूरोप के देशों तक परमाणु विकिरण का असर हुआ था और लोगों को सब्ज़ियों, दूध और दुग्ध उत्पादों से वंचित रहना पड़ा था। परमाणु विकिरण के कारण करीब चार हज़ार लोगों को कैंसर हो गया था। इसके अलावा 1, 50,000 वर्ग कि.मी. का इलाका प्रदूषित हो गया था और इसे लोगों से खाली कराना पड़ा था। साथ ही, हज़ारो कि.मी. भूमि बंजर हो गई। दुर्घटना के परिणामस्वरूप जो विकिरण हुआ, उसका विकृति पैदा करने वाला प्रभाव सैंकड़ों वर्षों में भी खत्म होने वाला नहीं। इतनी घातक है परमाणु उर्जा।

आज सुनामी और भूकंप के बाद जापान के फुकुशिमा में जो परमाणविक विकिरण हो रहा है, उसे रोक पाने में वहां के वैज्ञानिक और तकनीशियन अपने आप को अक्षम पा रहे हैं। इस विकिरण के प्रभावस्वरूप समुद्र का जल तक ज़हरीला हो रहा है, पता नहीं कैसे जापान इस विभीषिका पर नियंत्रण पा सकेगा जबकि द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान वह अकेला देश रहा है जिस पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराये थे और हिरोशिमा और नागाशाकी नामक दो शहरों को दहकते हुए लावे में बदल दिया था, पर पता नहीं क्यों यह देश साम्राज्यवादी अमेरिका का पिट्ठू बना हुआ है?

जो भी हो, बरसों पूर्व हुए चेर्नोबिल दुर्घटना और अभी तत्काल हुए फुकुशिमा दुर्घटना से सबक लेते हुए भारत सरकार को चाहिए कि वह परमाणु बिजली घरों की स्थापना का विचार छोड़ दे और अमेरिका के साथ किये गये परमाणु समझौते को रद्द कर दे। लेकिन अगर सरकार पर्यावरणवादियों और वामपंथियों के विरोध के बावजूद परमाणु संयंत्र स्थापित कर साम्राज्यवादी देशों से 'दलाली' खाने वाली योजनाओं पर अड़ी रहती है तो वह कभी न कभी जनता को कुंभीपाक नरक में डाल कर छोड़ेगी।

सरकार का तर्क है कि उसे विकास के लिए बिजली चाहिए, पर बिजली तो अन्य स्रोतों से भी मिल सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि परमाणविक बिजली काफ़ी महंगी पड़ती है और ख़तरनाक कितनी है, इसे दुहराने की आवयश्यकता नहीं है। इस संबंध में प्रसिद्ध वैज्ञानिक व सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता डॉ विवेक मोन्टेरो भारतीय परमाणविक वैज्ञानिकों से पूछते हैं कि क्या परमाणु बिजली देश के लिए सस्ती है। सरकार ने भी इस संबंध में चुप्पी साध रखी है और जनता को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं समझती। इस प्लांट को लगाने में कुल खर्चा 1,96000 करोड़ आयेगा। इस प्लांट में जहां प्रति मेगावाट बिजली का खर्च 19.5 करोड़ आयेगा, वहीं प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रियेक्टर लगाने पर खर्च आठ करोड़ रुपये प्रति मेगावाट आयेगा।

कोयले पर आधारित संयंत्र लगाने पर खर्च पांच करोड़ रुपये प्रति मेगावाट होता है। फ़िर सवाल है कि अरबों की लागत से बनने वाले परमाणु बिजली संयंत्र किस भाव पर प्रति यूनिट बिजली दे पायेंगे? इसके अलावा जनता को यह भी जान लेना चाहिए कि जिस तकनीक का प्रयोग करके इन परमाणु रियेक्टरों से बिजली बनाई जायेगी उसे ईपीआर (यूरोपियन प्रेशराइज्ड रियेक्टर) कहा जाता है, लेकिन इस तकनीक से पूरे विश्व में अभी कहीं भी बिजली नहीं बनाई जा रही है। इस तकनीक के केवल चार रियेक्टर अभी निर्माण की प्रक्रिया में हैं जिनमें से एक फिनलैंड में 2005 में और दूसरा स्वयं फ्रांस में 2007 में लगना शुरू हुआ था, पर इनमें डिज़ाइन की समस्यायें आ जाने के कारण इनके पूरा होने में अभी दो-चार साल का विलंब और होगा तथा इस दौरान इनकी लागत काफी बढ़ जायेगी। इस तथ्य को जनता से छुपाया जा रहा है कि इस तकनीक से बिजली उत्पादन में रेडियोएक्टिव पदार्थों का सामान्य से चार गुणा ज़्यादा उत्सर्जन होगा ओर जो कचरा निकलेगा, उसके निस्तारण की कोई सुरक्षित व्यवस्था हमारे पास नहीं है। इस संबंध में 'मज़दूर मोर्चा' के गत अंक में भी हम एक वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक के विचार प्रकाशित कर चुके हैं। दूसरी महत्त्वपूर्ण बात, क्या हमारे परमाणु संयंत्र भूकंप को सहने योग्य होंगे? क्या इन सवालों के जवाब साम्राज्यवादी देशों के दलाल बन चुके भारतीय शासकों के पास हैं?

भारत में कुल बिजली उत्पादन का मात्र तीन प्रतिशत ही परमाणु उर्जा से है और इसके लिए खर्च अरबों रुपये का है। इतनी लागत के बाद सस्ती परमाणु बिजली दे पाना किसी भी सूरत में संभव नहीं है। अत: सरकार को चाहिए कि वह अपनी हठधर्मिता छोड़े और जैतापुर हो अथवा कहीं भी परमाणु संयंत्र लगाने की परियोजनाओं को निरस्त करे, अन्यथा जनता के विरोध-प्रदर्शनों का सामना करने के लिए तैयार रहे।

- पी. सेवक

एटम बमों से अधिक ख़तरनाक हैं परमाणु बिजलीघर

कोयला से बिजली का उत्पादन बहुत प्रदूषण पैदा करता है जो दिखता भी है, दूसरे पूरी दुनिया में कोयले का भंडार सीमित है। डीज़ल से बिजली का उत्पादन महंगा तो है ही, प्रदूषण भी काफ़ी फ़ैलाता है। गैस से बिजली का उत्पादन बहुत ज़्यादा प्रदूषण फ़ैलाता है। कोयला-डीज़ल-गैस के भंडार समाप्ति की तरफ़ हैं। बांध बना कर जल से बिजली के उत्पादन में विस्थापन के लफड़े हैं, रख-रखाव के ज़्यादा खर्चे हैं, उत्पादन-क्षमता सीमित है, भूकंप की संभावना बढ़ती है। ऐसे में 'साफ़-सुरक्षित-अनंत काल' वाली परमाणु बिजली तारणहार......जापान में परमाणु बिजलीघरों द्वारा मचाई जा रही तबाही इस नौका को भी काग़ज़ी दिखा रही है।

सब सरकारें परमाणु बिजलीघरों में लगातार होते हादसों को छिपाती रही हैं, पर चेर्नोबिल का बड़ा हादसा छिपाया नहीं जा सका था और उसने परमाणु बिजलीघरों की 20 वर्ष नकेल कस दी थी। इधर परमाणु बिजलीघरों ने फ़िर से नाचना आरंभ ही किया था कि जापान में परमाणु बिजलीघर कहर ढाने लगे। परमाणु बिजलीघरों का कचरा तक बहुत ख़तरनाक है, हज़ारों वर्षों तक हानिकारक रहता है। परमाणु बिजलीघरों से ख़तरे किसी सीमा में नहीं बंधे हैं, इनकी कोई समय-सीमा भी नहीं है। यह संपूर्ण पृथ्वी को अपनी चपेट में लिये है, कई-कई पीढ़ियों तक मार करते हैं।

विकल्पों की, वैकल्पिक उर्जा के लिए छटपटाहट समस्या के तकनीकी समाधान की नई कोशिशें मात्र लगती हैं।

अनजाने में ग़लत हो जाना एक सामान्य बात है। लेकिन सभ्यता-प्रगति-विकास में जानते हुए ग़लत करने की परंपरा है। आज यह चंद लोगों तक सीमित नहीं है। आज जानते हुए ग़लत करना ने एक महामारी का रूप ले लिया है। इस-उस व्यक्ति-विशेष, संस्था-विशेष को दोष देना नादानी है अथवा अति कांइयापन है। मामला सामाजिक लगता है, सामाजिक मजबूरी का लगता है।

ऐसे में, बिजली की ही बात करें तो यह हमारी मजबूरी है। आज बिजली, बड़ी मात्रा में बिजली की आवश्यकता हमारी मजबूरी है, विनाशकारी मजबूरी है। ऐसी मजबूरियों से कैसे पार पायें?

फ़रीदाबाद मज़दूर समाचार, अप्रैल 2011

पेज 5 का शेष भाग

उगा वृक्ष
शांत निर्जन में
आकाश का ये कोना
और उसके नीचे
उगा वृक्ष
मेरे मित्र की भांति
मेरे साथ है
जो मुझसे बातें करते हैं
और मैं उनसे
....
धीमे-धीमे
पड़ती हैं फुहारें
वृक्ष और उसकी पत्तियां
एक सिहरन भर देती हैं
तन-बदन में
कभी वे उदास होते हैं
कभी खुश
ज्यों मेरे सुख-दुख में सहभागी हों
तुमसे बढ़ कर।

छाया
कमरे की खिड़की
के पास खड़क वृक्षों की
पत्तियों से छन कर आती धूप
मेरे तन-बदन पर
चमकती है
मानो शरद का उल्लास
व्यक्त कर रही हों
हल्की ठंड-छाया के साथ
....
शहर में ढल रही है शाम
लोग नदी के किनारे
सड़क पर, बाजार में
आत्म-व्यस्त हैं
....
पर यह धूप
सर्वत्र अपनी उल्लसित
छाया के साथ
ढल रही है
वह छाया मेरे मन में
कैद हो रही है
और मुझे सालती है
उस छाया को
किसी के साथ बांटने को।
संवादों में...
इन झाड़ियों में
कौन सी गंध है?
इन सूखे पेड़ों की
क्या दिनचर्या है?
ये सूखी घासें,
जो मुझे बुला रही हैं
और इन एकाकी क्षणों में
मुझसे बातें कर रही हैं,
का हश्र क्या होगा?
यह मेरी चिंता का विषय है
एक धीमी रोशनी
जो बिछ जाती है इन पर
शाम को गुम हो जाती है।
हर सुबह आती है
क्या वह कभी गुम हो जाएगी
फिर कैसे रहेगा
हमारा वजूद
इस नीले गगन के नीचे
यह धरती अंधेरे में डूब जाएगी
और रह जाएगी
इन झाड़ियों, पेड़ों और
सूखी घासों की स्मृतियां
जो हमें संवादों में ले जाती है।

ग़रीबों पर महंगाई की मार, अरबपतियों को टैक्स में छूट

गत वर्ष दिसंबर माह में लखनऊ में आयोजित 'योजनाबद्ध भ्रष्टाचार और ख़तरे में भारतीय लोकतंत्र' विषय पर सेमिनार में मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पत्रकार पी.साईंनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार कारपोरेट घरानों को हर वर्ष तकरीबन पांच लाख करोड़ रुपये की छूट देती है। यह कर माफ़ी आयकर, कस्टम और एक्साइज में होती है। सरकार कारपोरेट घरानों पर इतनी मेहरबान है कि पिछले साल 60 हज़ार करोड़ रुपये की आयकर में उन्हें छूट दी जो इस वर्ष बढ़ कर 80 हज़ार करोड़ रुपये हो गई।

बीपीएल पर मतभेद

सरकार ने योजना आयोग की उस सिफ़ारिश को स्वीकार किया है, जिसके मानदंड प्रत्येक राज्य में बीपीएल (ग़रीबी रेखा से नीचे) आबादी को उस प्रदेश की जनसंख्या की 36 फ़ीसदी तक सीमित कर देता है।

ग़रीबों की वास्तविक संख्या से यह आंकड़ा कतई मेल नहीं खाता। आयोग ने सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह सिफ़ारिश की है जिसका पहले ही काफ़ी विरोध हुआ है और सोनिया गांधी की अगुआयी वाली राष्ट्रीय विकास परिषद् ने भी इसे खारिज कर दिया है।

ग़रीबी के आंकड़ों को लेकर सरकार की अपनी ही एजेंसियों में मतभेद है, चाहे वह एन सी सक्सेना समिति हो, तेंदुलकर समिति हो या अर्जुन सेनगुप्ता समिति।